nationalisation of life Insuance business for the dissolution of the life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of Corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental there to

The motion was adopted

15.11 hrs.

PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now legislative business. Shri Dharamvir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : I beg to move .*

"That the bill to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, be taken into consideration."

वर्ष 1972 मे ग्रेज्युटि भुगतान अधिनियम बनाया गया था । इस अधिनियम में कारखानों खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनो रेल कंपनियों, दुकानों अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों का ग्रेज्युटि का भुगतान करने और इससे संबधित विषयों की व्यवस्था है । यह अधिनियम 16 सितम्बर, 1972 को लागू हुआ । पिछले 11 वर्षों के दौरान अधिनियम की कार्यप्रणाली में कुछ संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है । इस संबध में राज्य सरकारों, नियोजकों तथा कर्मकार संगठनों से बातों के साथ-साथ अधिनियम में संशोधन करने के लिए भी सुझाव प्राप्त हुए है । इस मामले पर जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था और सम्मेलन ने भी कुछ सिफारिश की थी ।

प्रस्तावित विधयक द्वारा अधिनियम मे किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है .

1. निर्वाह लागत में हुई वृद्धि के कारण मजदूरी स्तरों में जो बढोत्तरी हुई है, उसको दृष्टि में रखते हुए, उन सभी व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, जो सोलह सौ रुपए प्रति मास तक मजदूरी ले रहे है ।

2 सोलह सौ रुपए प्रति मास तक मजदूरी पाने वाले उन व्यक्तियों को भी, जो प्रशासनिक या प्रबधकीय हैसियत में नियोजित है, अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है । क्योंकि उन्हे ग्रेज्युटि का फायदा दिए जाने से इंकार करना भेदभावपूर्ण होगा, जबकि उतनी ही मजदूरी लेने वाले कर्मकारों को वह फायदा दिया जा रहा है ।

3. यह प्रस्ताव है कि मौसमी प्रतिष्ठानों के नियमित कर्मचारियों को गैर मौसमी प्रतिष्ठानों के नियमित कर्मचारियों के बराबर समझा जाए तथा उन्हे प्रति वर्ष पन्द्रह दिन के वेतन की दर से ग्रेज्युटि दी जाए ।

4 नियत्रक प्राधिकारियों का यह अधिकार दिए जा रहे है कि वे किसी दावे को स्वीकार करने और अन्य कानूनी मामलों के बारे में निर्णय दे ।

5 अधिनियम को अच्छी तरह से लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

सरकार को अधिनियम मे विशेष रूप से अधिनियम की धारा 2 (ग) में संशोधन करने के लिए कुछ और सुझाव प्राप्त हुये है इन की आवश्यकता मुख्य रूप से लालाप्पा लिंगाप्पा और अन्य बनाम "लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल्स

---

* Moved with the recommendation of the President.

मिल्स" शोलापुर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हुई और उन पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार का इरादा एक और विधेयक पेश करने का है अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शेष प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना संसद में पहले ही प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए, जो विवादास्पद प्रकृति का नहीं है। मुझे आशा है कि सदस्य इस विधेयक का स्वागत करेंगे।

मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावित विधेयक पर अब विचार किया जाए।

MR DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the bill to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, be taken into consideration.

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki) : Mr. Deputy Speaker, the amendment suggested to section 2 of the payment of Gratuity act 1972 is Rs. 1 600 in place of Rs. 1000/-. It is a welcome step, but by bringing this amendment for Rs. 1,600 the Ministary has not considered the present price level when compared to 1972. In fact this is bringing down the actual amount of salary when compared with 1972 price level. The price level has gone down, when compared to 1972, to 36 pies; that means to make it at par with Rs. 1000/-in 1972 level it has to be raised to Rs 2,778. Not only that, in most of these industries, a vast sections of workers are getting more than Rs.1,300 as salary. So they will not be covered by this amendment. So, my suggestion is that at least the Minister has to amend that provision of Rs.2,500-.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Why are you laughing ?

SHRI M M. LAWRENCE : It is not fantastic. You do not know the actual situation in the country. (*Interruptions*).

SHRI XAVIER ARAKAL (Frnakulam) : You do not have anything. That is the defferance between you and we.

SHRI M.M. LAWRENCE : I sympathise with you because you do not know the actual experience of workers who are working there. (*Interruptions*) In sub-section 3 of sectiou 4 of the principal Act, it has been stipulated that the amount payable to an employee shall not exceed 20 months' wages There is no rationale in continuing such a restriction. In so many industries already there are agreements to pay more than that. Even if they have served for more than 40 year, for the whole period, they will get this gratuity benefit. Even public sector industries have made an agreement with the workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Lawrence please wait for a few minutes. After that you can continue your speech.

Coming to the agenda, the Home Minister is to make a statement on Punjab and Haryana situation at 3-15 P.M.

15.15 hrs.

RE-STATEMENT ON PUNJAB AND HARYANA

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) Mr Deputy Speaker, as you remember, in the morning I explained to the Honourable speaker and to the Honourable House also that the hon Home Minister has written to the hon Speaker seeking some more time, to whichthe hon. Speaker gave his permission. So, now the Home Minister will make his statement as soon as he is ready.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcatta South) : When will he do it ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Home Minister has already written a letter to the Hon. Speaker also

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : One point may be clarified. When